लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3359
23 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कपड़ा मिलों को पुनर्जीवित करना

3359. श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कार्यशील और गैर-कार्यशील कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण कई कपड़ा मिलें निष्क्रिय/बंद पड़ी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कपड़ा मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त उद्देश्य के लिए तैयार की गई कार्य योजना और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या सरकार कपड़ा उद्योग को सहायता देने के लिए योजनाएं लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) सरकार द्वारा कपड़ा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): वस्त्र इकाइयों द्वारा वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई को प्रस्तुत की गई आवधिक सांख्यिकीय विवरणी के आधार पर, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य में कार्यशील तथा बंद स्पिनिंग मिलों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	कार्यशील मिलें	बंद मिलें (1976 से आज की तारीख तक)	कुल मिलें
1	महाराष्ट्र	135	64	199
2	तमिलनाडु	744	241	985

(ख): वस्त्र मंत्रालय के पास निजी वस्त्र मिलों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है जो कोविड-19 महामारी के कारण निष्क्रिय/बंद पड़ी हुई हैं। तथापि, कोविड-19 महामारी और मार्च, 2020 से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 23 कार्यशील मिलों में उत्पादन गतिविधि रोक दी गई थी। जनवरी, 2021 से, एनटीसी की कुछ मिलों में सामान्य प्रचालन पुन: शुरू किया गया है किंतु कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता और अन्य वित्तीय बाधाओं के कारण इन्हें जारी नहीं रखा जा सका। एनटीसी मिलों की निरंतर खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए, वस्त्र मंत्रालय नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के अधीन लोक उद्यम विभाग के परामर्श से इस मामले में आगे की कार्य योजना बना रहा है।

(ग) से (ङ): देश भर में बंद और रुग्ण स्पिनिंग मिलों के पुनरुद्धार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

सरकार प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र में उद्योग द्वारा नए निवेश पर फोकस कर रही है। इस उद्देश्य हेतु सरकार संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस), एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) जैसी अन्य योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। सरकार ने मानव निर्मित फाइबर, अपैरल, फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (वस्त्र के लिए पीएलआई) की शुरूआत की है। इसमें 19,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किए जाने की संभावना है। सरकार ने देश में 7 मेगा वस्त्र विनिर्माण पार्कों की स्थापना करने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना की भी शुरूआत की है। इससे व्यवस्था संबंधी लागत में कमी आएगी और भारतीय वस्त्र विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार आएगा। एक बार पूरा हो जाने पर ऐसे एक पार्क में प्रत्यक्ष रूप से एक लाख और परोक्ष रूप से दो लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है।

***